भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5031

बुधवार, 24 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

'मेक इन इंडिया'

5031. श्री मितेश रमेशभाई पटेल (बकाभाई):

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 'मेक इन इंडिया' में तेजी लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस संबंध में कोई ठोस एवं प्रभावकारी कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): भारत सरकार ने वर्ष 2014 में निवेश को सरल बनाने, नवाचार को बढावा देने, सर्वोत्तम विनिर्माण अवसंरचना बनाने, व्यवसाय को आसान बनाने और कौशल विकास को बढाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल शुरू की है। सरकार ने निवेश हेतु एक अनुकूल माहौल बनाने और मेक इन इंडिया में तेजी लाने के लिए कई पहल शुरू की हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश व्यवस्था का उदारीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया तथा देश में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के सेक्टरोल स्कीमें/कार्यक्रम शामिल हैं। इस मेक इन इंडिया पहल में 27 क्षेत्रों - 15 विनिर्माण क्षेत्रों तथा 12 चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य-योजना के प्रत्येक क्षेत्र में अवसंरचना को बढावा देने के उपाय, वित्तीय प्रोत्साहन और कौशल विकास आदि शामिल हैं। प्रत्येक क्षेत्र की कार्य-योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती है। इस पहल के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कई मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यम से समय-समय पर गतिविधियां भी शुरू की गई हैं। इन उपायों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

*****